

Scissor's Crisis /

कैची संकट का प्रारम्भ मई, 1922 के पश्चात हुआ।

कृषि पदार्थों की बाजार में शक्ति बढ़ने तथा औद्योगिक वस्तुओं को उत्पन्न करने से कृषि पदार्थों के मूल्यों में कमी, तथा औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने लगा गई थी।

कृषि तथा औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य-सूचकांकों को रेखाचित्र के रूप में प्रस्तुत किया जाये तो रेखाचित्र का रूप कैची के दो फलकों के समान हो जाता है।

ट्रोटरकी ने इसे कैची संकट की संज्ञा दी है।

कृषि तथा औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों में असंतुलन की प्रदर्शित करती है।

कृषि एवं उद्योगों के विकास में अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो गई थी।

मई 1922 के बाद औद्योगिक शक्ति के मानों में वृद्धि तथा कृषि उत्पादन के मानों में लगातार गिरावट से अक्टूबर 1923 में इन्का अनुपात 3:1 तक पहुँच गया था। कृषि मूल्य सूचकांक जो मई 1922 में 113 था, अक्टूबर, 1923 में चारकर कम हो 88 रह गया।

औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों का सूचकांक 74 से बढ़कर 175 हो गया।

निम्न तालिका कृषि व उद्योगों की वस्तुओं

दो मूल्यों में परिवर्तन को स्पष्ट करती है।

वर्ष कृषि मूल्य के सूचकांक औद्योगिक मूल्य के सूचकांक

(1913 = 100)

(1913 = 100)

मार्च 1922	113.0	74.0
अप्रैल 1922	100.5	99.0
सितम्बर 1922	94.0	112.0
अक्टूबर 1923	88.0	75.0

तालिका से स्पष्ट है कि कृषि और उद्योग-उत्पादन - मूल्यों के चार असंतुलन उत्पन्न हो गया।

मूल्यों सम्बन्धी यह परिवर्तन कम दूर कृषि मूल्यों के स्थान पर गिरते दूर कृषि मूल्य तथा गिरते दूर औद्योगिक मूल्यों के स्थान पर बढ़ते दूर।

कच्ची के फलको के समान रक्त - दूसरे के विपरीत दिशा में हुआ।

"कच्ची संकट" का नाम दिया गया।

कच्ची संकट के कारण : →

1. औद्योगिक उत्पादन में कमी : →

मार्च 1922 तक औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से उद्योगों में उत्पादन कम हो गया था। उत्पादन लगभग का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा था।

2. उदार सार्व - नीति : →

उदार सार्व-नीति से उद्योगों का विनियोग बढ़ा तथा संगठन प्रवृत्ति बढ़ी।

विनियोग बढ़ने तथा औद्योगिक भाव की विक्री-योग्य पूर्ति से कमी से मुद्रा-स्थिति उत्पन्न हो गई।

3. औद्योगिक उत्पादन - लागत में वृद्धि : →

राजकीय उद्योगों

में अव्यवस्था तथा अकुशलता

के कारण लागत वृद्धि ने औद्योगिक

मूल्यों को बढ़ाने में योग दिया।

4. कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि : →

मई 1922 में कृषि

पदार्थों के ऊँचे मूल्यों से कृषि में उत्पादन

को बढ़ावा मिला तथा फसल आने पर कृषि

पदार्थों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई।

भौगोलिक - लोचदार होने से मूल्यों में गिरावट

स्वाम्याधिकारी थी।

5. लाभ की प्रवृत्ति : →

बड़े-बड़े उद्योगों में

लाभ के लिए उत्पादन की नीति

के कारण भी औद्योगिक वस्तुओं के

मूल्यों में वृद्धि हुई।

6. दोषपूर्ण सरकारी नीति : →

कृषि पदार्थों के मूल्यों का निधारण

निम्न स्तर पर किया जाता था।

कृषक असंगठित थे, सरकार से उदार

सहायता के अभाव में अपनी उपज

को बेचने लिए बाध्य होता पड़ता था।

कँची संकट के उपाय : →

1. कृषि पदार्थों के मूल्यों में लगी के कारण कृषकों की आय में तेजी से कमी आयी
2. व्यापारिक संघ काफी सुदृढ़ रिश्ते में थे, निर्मित माल की बिक्री न हो पाने के कारण माल इकट्ठा होना चला गया।
3. उद्योगपतियों द्वारा निर्धन वर्ग का शोषण किया जाने लगा, वर्ग संघर्ष उत्पन्न हो गया।
4. उद्योगों में अति लाभ के कारण उद्योगों का उत्थरण व असंतुलित विकास सामने आया
5. श्रमिक व कृषकों में आपस में समबन्ध बिगड़ने लग गये, कृषकों श्रमिकों को अपना शोषक मानते थे।

कँची संकट के उपाय : →

1. आपात को प्रोत्साहित : →

सरकार ने विदेशों से औद्योगिक प्रयासों को दी जाने वाली वस्तुओं के आपात को प्रोत्साहित कर उनके उचित वितरण की व्यवस्था की। औद्योगिक श्रमजो के भावों में दृष्टि कम हो गई।

2. सार्व का नियंत्रण : →

स्टेट बैंक द्वारा औद्योगिक प्रयासों को दी जाने वाली सार्व व गणना की राशि सीमित कर दी गयी तथा व्याज की दर बढ़ दी गयी।
 औद्योगिक श्रमजो के भावों में दृष्टि कम हो गई।

3. मूल्य - नीति - निर्धारण : →

राज्य द्वारा देश में औद्योगिक उद्योगों को दी जाने वाली वस्तुओं के अधिकतम भाव - निर्धारित कर दिये गये तथा उद्योगों की लाभ - भागा में कमी करने के उपाय किये गए ।

4. समुचित वितरण व्यवस्था : →

सरकार ने व्यक्तिगत व्यापार को सीमित कर राजकीय व्यापार को बढ़ावा दिया ।

1922-23 में निजी व्यापार का भाग 78.8 प्रतिशत था, घटकर 1927-28 में 22.8 हो गया ।

5. औद्योगिक उत्पादन - लागत में कमी : →

उत्पादन लागत में कमी करने के लिए उद्योगों के व्यवस्था में कुशलता, अभिनवीकरण, वैज्ञानिक व्यवस्था और पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के उपलब्ध किये गये ।

6. कृषकों के लिए सारव की व्यवस्था : →

कृषकों को अपने भाव रोके रखने की दृष्टि से बैंकों ने उठे उदार शर्तों पर ऋण देने की व्यवस्था की कृषि पदार्थों की पूर्ति में कमी लाकर कृषि मूल्य में वृद्धि करना था ।

फलस्वरूप 1924 में इस संकट पर काबू पड़ लिया । औद्योगिक व कृषि पदार्थों के मूल्य का अनुपात और सितम्बर 1923 में 3:1 था, 1927 में घटकर 1.5:1 रह गया । धीरे - धीरे 1928 तक संकट पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया गया ।